शनिवार, 03 सितम्बर 2016

हिन्दुस्तान

आईआईटी में जुटेंगे कानून के विशेषज्ञ

कानपुर। आईआईटी में शनिवार से कानून विशेषज्ञों का जमावड़ा लगेगा। इसमे देश के साथ ही विदेशों के कानून विशेषज्ञ आएंगे। सभी द्वितीय इंटनेशनल कांफ्रेंस ऑन लॉ एंड इकोनामिक्स में आकर टिप्स देगे। यह जानकारी कोआर्डिनेटर डा. पीएम प्रसाद ने दी।

डा. प्रसाद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीस कांफ्रेंस का आयोजन आईआईटी कानपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर और आईआईएम अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। शुभारंभ जीएनएलयू गांधी नगर के निदेशक बिमल पटेल और प्रतियोगिता कमीशन ऑफ इंडिया की सचिव आईआरएस स्मिता जिनग्रान करेंगी।

वर्ल्ड में बेस्ट है इंडियन ज्यूडिशियरी सिस्टम

- आईआईटी में शुरू हुई सेकेंड इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन लॉ एण्ड इकोनॉमिक्स
- जर्मनी लॉ स्कूल के सीनियर प्रोफेसर ने दिए स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब

kanpur@inext.co.in

KANPUR (3 Sept): इंडियन ज्यूडिशियरी सिस्टम का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह दुनिया में बेस्ट है. यहां पर टाइम टू टाइम कोर्ट दखल देकर गवर्नमेंट को भी सावधान करती है. हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग बहुत अच्छी है. हालांकि इंडिया में लीगल केस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है. वहीं अफ्रीकन कंट्रीज व चाइना में गवर्नमेंट पावरफुल है, इसलिए वहां पर कोर्ट का कोई खास महत्व नहीं है.

भूमि अधिग्रहण में जिस तरह से इंडियन कोर्ट पब्लिक इंट्रेस्ट देखती है, वह काबिले तारीफ है. यह विचार आईआईटी में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन लॉ एण्ड इकोनामिक्स 2016 में शिरकत करने आए जर्मनी के बी लॉ स्कूल के प्रोफेसर एच ब्रेंड शेफर ने व्यक्त किए.

PIC: I NEXT

दीप प्रज्जवलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

भूमि अधिग्रहण पर सही रुख

इंटरनेशनल कांफ्रेंस का इनॉग्रेशन आईआईटी के डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर्स प्रोफेसर के. मुरलीधर ने दीप जलाकर किया. जर्मन प्रो. शेफर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण गवर्नमेंट सेक्टर व प्राइवेट सेक्टर दोनों ही करते हैं. प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसा देता है. जबकि गवर्नमेंट सेक्टर से एक लिमिट में मुआवजा मिलता है. जिसकी भूमि गवर्नमेंट लेती है तो वह कोर्ट में दस्तक देता है. कोर्ट यह देखता है कि इसमें जनहित कितना है, उसके बाद डिसीजन दे दिया जाता है. यह एक अच्छी प्रक्रिया है.

कॉम्पटीशन एक्ट बेहद अहम

सेक्रेट्री सीसीआई आईआरएस स्मिता झिंगरन ने कहा कि कॉम्पटीशन एक्ट की भूमिका काफी अहम हो गई है. यह इयर 2002 में बनाया गया था और इयर 2009 में लागू हुआ था. इस एक्ट की खासियत यह है कि बड़ी कंपनियां मनमानी करके अपने प्रोडक्ट हाई रेट्स पर नहीं बेच सकती हैं. एनसीआरडीसी डॉ. बीसी गुप्ता ने कहा कि वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हर संभव कोशिश करते हैं. सभी एक्सपर्ट का मानना है कि अब यूरोपियन कंट्रीज की तरह इंडिया में लॉ और इकोनामिक्स का कोर्स यूनिवर्सिटीज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शुरू किए जाने चाहिए.

आईआईटी की राह चलेगा आईआईएम

» आईआईएम अहमदाबाद के डीप ऑफ फैकल्टी अफेयर्स प्रो. एरोल डिसूजा ने कहा बढ़ सकती है आईआईएम में फीस

kanpur@inext.co.in

KANPUR (4 Sept): आईआईटी में फीस बढ़ोत्तरी के बाद अब आईआईएम भी उसी राह चल पड़ा है. आईआईएम अहमदाबाद में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिव्यू किया जा रहा है.

बड़े शिक्षाविद जुटे

इसकी जानकारी आईआईटी कानपुर में चल रही इंटरनेशनल कांफ्रेंस में आए आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर्स प्रो. एरोल डिसूजा ने दी. लॉ एंड इकोनामिक्स पर आयोजित इस इंटरनेशनल कांफ्रेंस में देश भर से कई बड़े शिक्षाविद जुटे थे. प्रो. डिसूजा ने बताया कि आईआईएम में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए संसाधनों की जरूरत बढ़ गई है.

My City
कानपुर अमर उजाला
रविवार | 4 सितंबर

फोरम में बिल्डरों की शिकायतें ज्यादा

'सेकेंड इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन लॉ एंड इकोनॉमिक्स 2016' का आईआईटी में आगाज

आईआईटी में सेकेंड 'इंटनरेशनल कांफ्रेंस ऑन लॉ एंड इकोनॉमिक्स 2016' में (दाएं से बाएं) डा. राम सिंह डीएसई नई दिल्ली, एनसीआरडीसी के सदस्य डा. एसएम कांतिकार, गुजरात नेशनल लॉ कॉलेज के डायरेक्टर प्रो. बिमल एन पटेल, आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. इरोल डीसूजा, डीन फैकल्टी अफेयर्स प्रो. के मुरलीधर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी स्मिता झीनग्रान, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन (एनसीआरडीसी) के सदस्य डा. बीसी गुप्ता और जर्मनी के प्रो. मार्टिन।

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन (एनसीआरडीसी) के सदस्य डा. बीसी गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा बिल्डर ही परेशान करते हैं। पिछले कुछ सालों में बिल्डरों की सबसे ज्यादा शिकायतें उपभोक्ता फोरम में आई हैं। अगर कंज्यूमर पूरी तरह से जागरूक हो जाए तो ऐसी समस्याएं रुक सकती हैं। आईआईटी में सेकेंड 'इंटनरेशनल कांफ्रेंस ऑन लॉ एंड इकोनॉमिक्स 2016' में उन्होंने कंज्यूमर एक्ट पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री गुप्ता ने बताया कि अब यूएनओ ने भी कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट पास कर दिया है। अब इसका पालन यूएनओ से संबंधित सभी देशों को करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कंज्यूमर के मामले की सुनवाई किसी भी हालत में तीन माह के अंदर हो जानी चाहिए। गुप्ता ने अन फेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।

जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा तभी रुकेगा उत्पीड़न

एनसीआरडीसी के सदस्य ने कंज्यूमर एक्ट की बारीकियों पर डाला प्रकाश

देशभर के तकनीकी, विधिक और आर्थिक मामलों के जानकारों का लगा जमावड़ा

जर्मन प्रोफेसर बोले, भारतीय अधिग्रहण बिल मजबूत

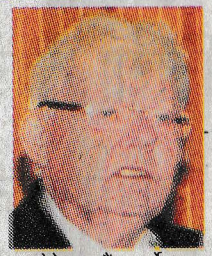

प्रोफेसर हैंस बर्नेड स्कैफर

ब्यूसिरियस लॉ स्कूल, जर्मनी के प्रोफेसर हैंस बर्नेड स्कैफर ने एक सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कहा कि दुनिया भर के नेता एक समान हैं। सब पहले अपने लिए सोचते हैं फिर किसी और के लिए। उनकी सोच हर जगह समान है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भूमि अधिग्रहण के लिए अलग-अलग नियम कानून हैं। चीन, फ्रांस जैसे कई ऐसे देश हैं जहां अधिग्रहण के लिए मुआवजा नीति सही नहीं है। इस मामले में भारत सबसे मजबूत है। उन्होंने भारतीय अधिग्रहण बिल को जर्मनी से भी मजबूत बताया।

प्रतिस्पर्धा से मजबूत होंगे आर्थिक हालात

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी स्मिता झीनग्रान ने उद्योग जगत में स्वस्थ और मजबूत प्रतिस्पर्धा को देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ही कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को लागू किया गया। यह देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है और प्रत्येक देशवासियों को इस कानून के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।

कांफ्रेंस में बैठे आईआईटी के स्टूडेंट।

कांफ्रेंस को एनसीआरडीसी के दूसरे सदस्य डा. एसएम कांतिकार ने भी संबोधित किया। उन्होंने डॉक्टर और मरीज के संबंधों के बारे में बताया। कहा कि कई मामले ऐसे आते हैं जहां डाक्टर बेईमानी कर मरीज को धोखा देता है। यह

कानपुर जागरण

एक नजर

कर्मचारियों को यूनीफार्म न दी तो खत्म होगा अनुबंध

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. नवनीत कुमार सक्रिय हो गए हैं। रविवार रात 11.30 बजे प्राचार्य अचानक हैलट इमरजेंसी पहुंचे। उस समय इमरजेंसी में मरीजों की भारी भीड़ थी। डाक्टर मरीजों का इलाज करने में जुटे थे। आउट सोर्सिंग कंपनी के सफाई कर्मचारी एवं वार्ड ब्वाय बगैर यूनीफार्म के ड्यूटी कर रहे थे। इस पर प्राचार्य ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों को यूनीफार्म नहीं दी तो अनुबंध ही निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो घंटे में 12 गंभीर मरीज इमरजेंसी में भर्ती हुए थे।

नये मतदाताओं के लिए लगाया कैंप

भाजपा कौशलपुरी मंडल के पदाधिकारियों ने नये मतदाताओं के लिए कैंप लगाया। जानकारी के मुताबिक 327 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। इस दौरान रवि जायसवाल, महेंद्र नाथ शुक्ला, मनोज पांडेय, शोभा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं। उधर नमामि गंगे समिति पदाधिकारियों द्वारा रविवार को नये मतदाता बनाओ अभियान शुरु किया गया। 176 लोगों ने यहां आकर नये मतदाता बनने संबंधी फार्म भरे। इस मौके पर जिला संयोजक विजय गौड़, श्रीकृष्ण दीक्षित, संदीप मिश्रा, हिमांशु गुप्ता आदि मौजूद रहे।

छात्रसंघ चुनाव कराये जायें

छात्रसंघ चुनाव पर जिन कारणों से रोक लगी है। उसे हटाया जाये। छात्र संघ चुनाव को कराया जाना चाहिए। यह बात पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूथ इंटक प्रशांत शुक्ला ने पत्रकारों से वार्ता कर कही।

विदेशों में भी कोख पर पहरा, बेटियों पर संकट

- भारत की तरह चीन व कोरिया में लिंग जानना चाहते हैं 70 लाख लोग

कानपुर : भारत की तरह चीन व कोरिया में भी पैदाइश से पहले लोग लिंग जानने की ख्वाहिश रखते हैं। इसका कारण वहां पर भी लोग पुत्र को लेकर संजीदा हैं। एक सर्वे में ऐसे 70 लाख लोग सामने आए हैं जो पैदाइश से पहले लिंग जानने की चाहत रखते हैं। यह बातें कॉर्नेल लॉ स्कूल के प्रोफेसर शीतल कालांतरी ने आईआईटी में आयोजित लॉ एंड इकोनोमिक्स विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कहीं प्रो. कालांतरी स्काइप के माध्यम से आईआईटी के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में क्राइम अगेंस्ट वूमेन विषय पर अपना व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत के लोग आज दुनिया भर में रह रहे हैं। विदेशों में बच्चा पैदा होने से पहले लिंग के बारे में जानने की चाहत रखने वालों में उनकी संख्या सर्वाधिक है। इससे लिंग अनुपात कम हो रहा है।

विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों से आए छात्रों ने पूछे सवाल

प्रो. कालांतरी के व्याख्यान के बाद देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों से आए छात्र-छात्राओं ने लिंगभेद को लेकर कई सवाल पूछे। उनके सवालों का जवाब देते हुए प्रो. कालांतरी ने कहा कि लिंग भेद खत्म करने के लिए विदेशों में भी जागरूकता की जरूरत है। वहां पर रहने वाले लोगों में कुछ ही लोग इस सोच के जरूर हैं लेकिन समय के साथ अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो लिंग अनुपात और बिगड़ेगा।

आईआईएम में बढ़ सकती है फीस

- आईआईएम अहमदाबाद का वित्त विभाग कर रहा रिव्यू
- लॉ एंड इकोनॉमिक्स पर व्याख्यान देने पहुंचे प्रो. डिसूजा

कानपुर, जागरण संवाददाता : आईआईटी के बाद अब आईआईएम भी फीस बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा है। संसाधनों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान फीस को लेकर आईआईएम अहमदाबाद का वित्त विभाग रिव्यू कर रहा है। यह जानकारी आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ फैकेल्टी अफेयर्स प्रो. एरोल डिसूजा ने आईआईटी में दी। लॉ एंड इकोनॉमिक्स विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देने पहुंचे प्रो. डिसूजा ने बताया कि हालांकि पिछले वर्ष आईआईएम ने फीस बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है।

आईआईएम में शैक्षिक गुणवत्ता कायम रखने के लिए संसाधनों की जरूरत बढ़ रही है। प्रबंधन के इस विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थान के छात्र इतने मेधावी होते हैं कि उन्हें लाखों रुपए का एजुकेशन लोन चुकाने में अधिकतम दो वर्ष का समय लगता है। प्रो. डिसूजा ने बताया कि अगर जरूरतमंद छात्र उनके संस्थान में प्रवेश लेने के लिए आता है तो वे उन्हें तीन वर्ष की पूरी पढ़ाई में छूट मिलती है। आने वाले समय में आईआईएम की फीस दस फीसद तक बढ़ाई जा सकती है।

जॉब ऑफर करने के बाद नौकरी न देने पर 80 फीसद की रिकवरी ली : इकोनोमिक विभाग में प्रोफेसर व डीन ऑफ फैकेल्टी अफेयर्स प्रो. एरोल डिसूजा ने बताया कि आईआईएम के छात्रों को जॉब ऑफर करने के बाद नौकरी न देने पर फ्लिप कार्ड को चेतावनी देने के साथ चार माह के वेतन का 80 फीसद रिकवरी के रूप में लिया गया है। अगर भविष्य में कंपनी ऐसा करती है तो उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रो. एरोल डिसूजा

न्यायाधीश की नियुक्ति पर चर्चा जरूरी

आईआईटी के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे शिक्षाविदों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत महसूस की। उनका मानना है कि देश के न्यायालयों में उतनी तेज गति से काम नहीं हो रहा है जितनी जनता को जरूरत है। न्यायाधीश की नियुक्ति पर नियम में बदलाव की जरूरत है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

लॉ और मेडिकल कोर्स न होने से पिछड़ा आईआईटी

- आईआईटी खडगपुर में लॉ की पढ़ाई हुई शुरू, मेडिकल की चल रही तैयारी

कानपुर, जागरण संवाददाता : लॉ एंड इकोनॉमिक्स विषय पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षाविदों ने इन दोनों विषयों को महत्वपूर्ण बताते हुए आईआईटी के पाठ्यक्रमों में भी शामिल करने की बात कही। सम्मेलन में पहुंचे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शरविंदु पांडेय ने बताया कि लॉ व इकोनॉमिक का कोर्स अब सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। आईआईटी खडगपुर में लॉ की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जबकि मेडिकल की तैयारी चल रही है। कानपुर में इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के साथ इकोनॉमिक्स का कोर्स संचालित है। लेकिन अभी भी कई अन्य कोर्स लांच करने की जरूरत है। आईआईटी कानपुर से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट विषय में पीएचडी करने वाले डॉ. पांडेय ने बताया कि इंस्टीट्यूट स्तर पर होने वाले सर्वे में तो आईआईटी अपना स्थान बना लेते हैं लेकिन सीमित कोर्स होने के कारण विश्वविद्यालय की रैंकिंग में यह पिछड़ जाते हैं। आईआईटी खडगपुर व आईआईटी कानपुर दोनों बड़े कैंपस हैं। इनमें जमीन की कोई कमी नहीं है। बड़े कैंपस होने के कारण नए नए कोर्स शुरू करना यहां पर बहुत आसान है।

डा. शरविंदु पांडेय

आईआईटी में होगी मेडिकल की पढ़ाई

ग्लोबल ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार की वजह से पहल

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार और ग्लोबल ब्रांडिंग के उद्देश्य से आईआईटी ने पढ़ाई का तरीका बदला है। अब इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई पर भी फोकस किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो आईआईटी कैंपस में बैचलर ऑफ मेडिसिन (मेडिकल) की पढ़ाई भी होगी। आईआईटी खड़गपुर ने तो मेडिकल की पढ़ाई का खाका तैयार कर लिया है। आईआईटी कानपुर भी तैयारी में है।

आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की दो दिवसीय (तीन-चार सितंबर) इंटरनेशनल कांफ्रेंस लॉ एंड इकोनॉक्सि कार्यशाला का समापन हुआ। आईआईटी कानपुर से पीएचडी करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शरदिंदु पांडेय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हर फैकल्टी की पढ़ाई होती है। इसी वजह से भारतीय तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थान पिछड़ जाते हैं। अब आईआईटी कानपुर ने इंजीनियरिंग और साइंस के साथ ही इकोनॉमिक्स, ह्यूमनिटीज, मैनेजमेंट (एमबीए) और लॉ की पढ़ाई पर जोर दिया है। इसका सकारात्मक नतीजा देखने को मिलेगा। आईआईटी की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी सुधार होगा। आईआईटी कानपुर के पास काफी जमीन है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए फैकल्टी खोली जा सकती है। इस पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी सहमत है। आईआईटी कानपुर के प्रो. उदय सिंह रचेला ने गेस्ट को धन्यवाद दिया।

डॉ. शरदिंदु पांडेय

साइंस, इंजीनियरिंग के साथ ही इकोनॉमिक्स, ह्यूमनिटीज, मैनेजमेंट, लॉ की पढ़ाई पर जोर

'मंत्रालय से हो जजों की नियुक्ति'

अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस लॉ एंड इकोनॉमिक्स में शिक्षाविदों ने जजों की नियुक्ति पर चर्चा की। आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ फैकल्टी प्रो. एरोल डिसूजा ने अपनी राय रखी और कहा कि जजों की नियुक्ति कानून मंत्रालय से होनी चाहिए। अमेरिका और चाइना सहित दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है। भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जहां जजों की नियुक्ति सुप्रीमकोर्ट से होती है। शिक्षाविद ने कहा कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया आम जनता के लिए है लेकिन इसमें काफी समय लगता है। मामलों का सामान्य निस्तारण भी सात साल में होता है। दुनिया के अन्य देशों में यह समयसीमा एक साल से डेढ़ साल की है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी से आर्थिक नुकसान होता है।

प्रो. एरोल डिसूजा

दाल की महंगाई अस्थायी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के एक्सपर्ट पैनल के सदस्य और आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ फैकल्टी प्रो. एरोल डिसूजा ने कहा कि अरहर के दाल की महंगाई अस्थायी है। अब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। दाल से प्रोटीन मिलती है, इसलिए डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आ गया। अब जरूरत सप्लाई चेन (प्रोडक्शन और आपूर्ति) को दुरुस्त करने की है। प्रो. डिसूजा ने कहा कि एक महीने में ही दाल की महंगाई सामान्य हो जाएगी। अभी प्रति किलो दाल का रेट 100-110 रुपये किलो है।

विदेशों में भी बेटे की चाहत

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चाइना और इंग्लैंड सहित तमाम देशों में बेटे-बेटी का भेदभाव है। यह कहना है कारनल यूनिवर्सिटी अमेरिका की क्लीनिकल प्रोफेसर ऑफ लॉ प्रो. शीतल कालंट्री का। वह स्कॉइप की मदद से आईआईटी की अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। प्रो. शीतल ने कहा कि अब विदेशी भी बेटे की चाहत रखते हैं। बेटी पैदा होने पर निराश होते हैं। यह स्थिति खतरनाक है। सोच में बदलाव नहीं हुआ तो जेंडर गैप बढ़ेगा। इसका खामियाजा समाज के हर तबके को भुगतना पड़ेगा।

बढ़ सकती है आईआईएम की फीस

आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ फैकल्टी प्रो. एरोल डिसूजा ने जताई संभावना

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) की पढ़ाई महंगी हो सकती है। शैक्षिक सत्र 2016-17 से ही फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी है। ऐसा हुआ तो आईआईएम की फीस सालाना साढ़े 13 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगी। अभी सालाना फीस साढ़े 12

कहा, फीस स्ट्रक्चर का रिवीजन किया जा रहा

साढ़े 13 लाख से ज्यादा हो जाएगी सालाना फीस, अभी साढ़े 12 लाख के आसपास

यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस लॉ एंड इकोनॉमिक्स में हिस्सा लेने आए थे।

ये हैं आईआईएम

लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलूरू कर्नाटक, कोझीकोड केरला, इंदौर, शिलांग, रोहतक, रांची, रायपुर, त्रिचि तमिलनाडु, काशीपुर उत्तराखंड, उदयपुर राजस्थान, नागपुर महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बोध गया बिहार, अमृतसर पंजाब, संभलपुर ओडिशा, सिरमौर हिमाचल प्रदेश

फ्लिपकार्ट से वसूला जुर्माना

स्टूडेंटों को जॉब देकर ज्वाइनिंग न देने वाली ऑनलाइन मार्केटिंग की मल्टीनेशनल कंपनी फ्लिपकार्ट पर आईआईएम अहमदाबाद ने जुर्माना ठोका है। डीन ऑफ फैकल्टी प्रो. एरोल डिसूजा ने बताया कि कंपनी ने मैनेजमेंट के नौ स्टूडेंटों को जॉब दी थी लेकिन चार महीने तक ज्वाइनिंग नहीं दी। इसके बाद कंपनी से बात की गई और सेलेक्टेड स्टूडेंटों को 80 फीसदी सैलरी (चार महीने की) बतौर जुर्माना देने का आदेश दिया गया। इस पर कंपनी तैयार हो गई। डीन ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने दोबारा ऐसा किया तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा।

22 तक भरें ऑनलाइन फार्म

आईआईएम में एडमिशन के कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के ऑनलाइन फार्म 22 सितंबर को शाम पांच बजे तक भरे जा सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 18 अक्तूबर से मिलेगी। चार दिसंबर को टेस्ट कराया जाएगा। इसका एग्जाम सेंटर कानपुर के पीएसआईटी में भी बना है। जनवरी 2017 के दूसरे सप्ताह में कैट का रिजल्ट आएगा।

अफ्रीका और चीन में कोर्ट से ज्यादा सरकारें हावी, वहां बेहतर ढंग से नहीं हो पाता भूमि अधिग्रहण

भारत में चाइना से ज्यादा मजबूत कानून

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

भारत का भूमि अधिग्रहण कानून अफ्रीका और चाइना से ज्यादा मजबूत है। यहां पर भूमि अधिग्रहण विदेशों की अपेक्षा ज्यादा आसान है। भारत का बिल नया है इसीलिए वह ज्यादा प्रभावशाली भी है। चाइन व अफ्रीकी देशों में कोर्ट और कानून से ज्यादा अधिकार सरकारों के पास हैं इसीलिए भूमि अधिग्रहण बिल का सही पालन नहीं हो पाता। ये बातें आईआईटी में जर्मनी के बूसीरियस लॉ यूनिवर्सिटी के प्रो. और कीनोट स्पीकर प्रो. हैंस बर्न्ड ने शनिवार को रखीं।

आईआईटी कानपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आईआईएम अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कानून और अर्थशास्त्र वर्कशॉप शुरू हुई। निदेशक जीएनएलयू प्रो.बिमल एन पटेल ने कहा कि भारत के पीएम का वियतमान का दौरा लॉ एंड इकोनॉमिक्स को देखते हुए ही है। वहां पर नैचुरल गैस पर काफी काम हुआ है। भारत को इससे काफी फायदा होगा। प्रतिस्पर्धा आयोग की सचिव स्मिता झिंगरन ने कहा कि अर्थशास्त्र बड़ी फील्ड है। हमारा देश डेटा में कमजोर है।

नेशनल उपभोक्ता विवाद समाधान कमीशन के सदस्य डा.बीसी गुप्ता ने कहा कि बाजार में उपभोक्ताओं को बचाने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। दूसरे सदस्य डॉ. एसएम कानिटकर ने डॉक्टर मरीज संबंधों पर कहा कि विवाद की जड़ विश्वास है, जो किसी भी प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आईआईटी कानपुर के एक्टिंग डायरेक्टर के मुरलीधर ने कहा कि कानून और अर्थशास्त्र विकास के स्रोत हैं। प्रो. पीएम प्रसाद ने अतिथियों का स्वागत किया।

आईआईटी में कानून और अर्थशास्त्र पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें कानून के दिग्गजों ने दिए कई टिप्स।

प्रतिस्पर्धा एक्ट से छोटे उद्योगों को फायदा

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सचिव स्मिता झिंगरन ने कहा कि 2002 में प्रतिस्पर्धा एक्ट बनाकर उसे 2009 में प्रभावी बनाया गया है। इससे छोटे उद्योगों को खासा फायदा हो रहा है। अभी तक बड़े उद्योग छोटों को दबाकर मनमानी करते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। साफ प्रतिस्पर्धा होगी, इससे छोटे उद्योगों को फायदा होगा।

भारत सुप्रीम कोर्ट विश्व में सर्वश्रेष्ठ

जर्मनी के बूसीरियस लॉ यूनिवर्सिटी के प्रो. हैंस बर्न्ड ने कहा कि भारत का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इसकी तुलना पूरे विश्व में होती है। यहां बड़ी संख्या में कानूनी मामलों का लम्बित होना जरूर एक समस्या है। अगर मामले जल्द निपटा लिए जाएं तो भारतीय अदालतों की तुलना हो ही नहीं सकती है।

जल्द मिलेगा न्याय

नेशनल उपभोक्ता विवाद समाधान कमीशन के सदस्य डा.बीसी गुप्ता ने कहा कि 22 दिसंबर 2015 को यूएनओ ने उपभोक्ता संरक्षण प्रस्ताव पास कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं जल्द न्याय और सुरक्षा मिलेगी। यूएनओ महासचिव अक्तूबर में एक्सपर्ट्स की मीटिंग करने जा रहे हैं। उपभोक्ता अधिकार एक्ट यूके ने पास किया है। भारत सरकार भी नया एक्ट बनाने जा रही है।

एक और बेटी ने बढ़ाया मान

कानपुर। एक तरफ पीसी सिंधु और साक्षी मलिक ने ओलम्पिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है तो हिमाकृति। दूसरी तरफ शहर की होनहार बेटी हिमाकृति ने आईसीएससी बोर्ड की अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में जीतकर शहर का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में देशभर से डेढ़ लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था।

आईसीएससी के संस्थापक एल्बर्ट एरो की स्मृति में बोर्ड हर वर्ष क्रिएटिव राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करता है। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाती है। शीर्ष दस सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले स्टूडेंट्स में से एक शहर की हिमाकृति भी हैं। कानपुर में पहली बार किसी छात्रा को ये सम्मान मिला है। शीलिंग हाउस में कक्षा 11 की छात्रा हिमाकृति के पापा आयकर विभाग के सहायक आयुक्त हरीश भाटिया हैं। उनकी मां शशिप्रभा एसबीआई में रीजनल मैनेजर हैं।

कैम्पस लाइव

LIVE को

आपके स्कूल, कॉलेज या कैम्पस में कोई गतिविधि हों, या जानकारी देना चाहते हों तो हमें ईमेल करें, kanpur@livehindustan.com P

सीएसजेएमयू में शनिवार को छात्रसंघ चुनाव के

सीएसजेएमयू कराए छात्रस

कानपुर। छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर डी ने शनिवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्व छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय चुनाव क है। कुलपति प्रो. जेवी वैशम्पायन को ज्ञापन दे मांग की गई। छात्रों का कहना है कि छात्रसंघ ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है इसके उदासीनता दिखा रहा है। इस मौके पर आकाश ठाकुर, तरुण ठाकुर, दीपक पंडित, उत्कर्ष ति

पनकी में साइकिल यात्रा पर निकले डॉ. आलोक

एचबीटीयू के शनिवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद खुशी मनाते छात्र।

एक नजर में चुनाव की स्थिति

• हॉबी क्लब-सौरव तोमर 539, आदित्य नाथ त्रिपाठी 515 • योगा क्लब- अनूप मिश्रा 704, भानु प्रताप सिंह 487 • फोटोग्राफी क्लब- कबीर रजा 844, अमरदीप पांडे 708 • लिट्रेरी सब काउंसिल- अमित बत्रा 931, पार्थसार्थी यादव 613 • कल्चर सब काउंसिल- रजत श्रीवास्तव 1003, आचिन्त्य मिश्रा 457 • स्पोर्ट्स सब काउंसिल- आदित्य

15 हजार के हाथ से गई छात्रवृत्ति

बीएड

कानपुर | हिन्दुस्तान संवाद

सत्र 2015-17 में प्रवेश लेने वाले पंद्रह हजार से अधिक बीएड छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी तक परीक्षाएं न होने की वजह से छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ही नहीं कर पाए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से

शासन चाहे तो मिल सकता है मौका

विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन छात्रों को शासन स्तर पर मौका दिया जा सकता है क्योंकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं हैं। दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में छात्र फंसे हुए हैं। इनकी मांग तेज की जाए तो आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है।

आईआईटी में 'लॉ एंड इकानॉमिक्स' के विभिन्न आयामों पर मंथन

■ कानपुर।

आईआईटी में 'लॉ एंड इकानॉमिक्स' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन के बाद व्याख्यान सत्र में विषय विशेष के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गयी। इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन समाज में बदल रहे व्यवहार के मद्देनजर उपयोगी प्रभावी वैधानिक नियमों के निर्धारण विमर्श के उददेश्य से किया गया है,ताकि आर्थिक विकास की बाधायें दूर कर तेज प्रगति को अंजाम दिया जा सके। इस सेमिनार का आयोजन आईआईटी कानपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनवर्सिटी व आईआईएम अहमदाबादा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।

प्रो.एसबी सैचेफर

दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में जुटे देश-दुनिया के कानूनी दिग्गज व शिक्षाविद्

सेमिनार का उद्घाटन आईआईटी के कार्यवाहक निदेशक डॉ.मुरली धर ने किया। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि थीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की सचिव आईआरएस स्मिता झिंगरन, जबकि मुख्य संबोधन ब्यूकेरियस लॉ यूनिवर्सिटी, हैंबर्ग (जर्मनी) के प्रो.एसबी सैचेफर का था। प्रो.सैचेफ र ने सिंगूर भूमि अधिग्रहण विवाद के दृष्टिगत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न देशों के कानूनों की चर्चा की व कहा कि इसके लिए कोई एक समान फार्मूला विकसित करना मुश्किल हो सकता है। यह विभिन्न देशों में भूमि उपलब्धता व उसके निजी-सरकारी स्वामित्व पर निर्भर करता है। उन्होंने लॉ एंड इकानॉमिक्स से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं को विस्तार से स्पष्ट किया। सह संयोजक आईआईटी प्रो.पी.मुरलीधर ने बताया कि सेमिनार के अंतर्गत दूसरे दिन रविवार को भी विषय विशेष पर मंथन का दौर जारी रहेगा व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। शनिवार को सेमिनार में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सदस्य आईएएस बीसी गुप्ता ने 'अनफेयर ट्रेड्स' विषय पर केन्द्रित अपना व्याख्यान दिया। उक्त कमीशन के ही सदस्य डॉ.कांतिकर सहित अन्य वक्ताओं ने भी सेमिनार को संबोधित किया।सेमिनार में मंथन के लिए चयनित विषयों में लॉ एंड इकानॉमिक्स आफ प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ, इनवायरन्मेंटल चैलेंजेज, कंज्यूमर कांट्रैक्ट्स, क्राइम अगेंस्ट वूमेन्स, लॉ एंड फ इनेंस, कंस्टीट्यूशन फंक्शनरीज एंड द पब्लिक ट्रस्ट सहित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के लिए दुनिया भर से पेपर आमंत्रित किये गये है, जिन पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्तावों-सुझावों का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा।

लॉ एंड इकोनॉमिक पढ़ें, समस्याएं छूमंतर

आईआईटी में आयोजित लॉ एंड इकोनॉमिक्स विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते डीन आफ फैकेल्टी अफेयर्स प्रो. के मुरलीधर।

कानपुर, जागरण संवाददाता : किसानों की जमीन के मुआवजे से लेकर इंफोमेशन टेक्नोलॉजी तक का क्षेत्र कानून व अर्थशास्त्र से जुड़ चुका है। कानून व अर्थशास्त्र के बगैर एकसाथ रहे चुनौतियों से निपटना नामुमकिन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों में लॉ एंड इकोनॉमिक्स के संयुक्त कोर्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। भारत के विश्वविद्यालयों को भी इस पाठ्यक्रम की जरूरत है।

आईआईटी में लॉ एंड इकोनॉमिक्स विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बुसरिस लॉ यूनिवर्सिटी जर्मनी के प्रो. हैंस बर्न्ड शेफर ने इस पर प्रकाश डाला। कहा कि यह दोनों कोर्स मिलकर समाज की समस्याएं हल कर रहे हैं। तकनीकी, प्रबंधन, प्रशासन व समाजिक मामलों का हिस्सा बन चुके लॉ एंड इकोनोमिक्स के संयुक्त पाठ्यक्रम की पढ़ाई अमेरिकाँ व जर्मनी जैसे देशों में कर रहे हैं। सम्मेलन में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रो. बिमल एन पटेल, आईआईएम अहमदाबाद के डीन ऑफ

◆ विदेशी विश्वविद्यालयों में शुरू हो चुकी है संयुक्त कोर्स की पढ़ाई

फैकेल्टी अफेयर्स प्रो. एरोल डिसूजा व आईआईटी के डीन ऑफ फैकेल्टी अफेयर्स प्रो. के मुरलीधर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

भारत की न्याय व्यवस्था बेहतरीन : प्रो. शेफर ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अच्छी है। भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों का निस्तारण करते समय यहां की न्याय व्यवस्था के चलते किसानों को उचित मुआवजा मिलता है। बस न्याय व्यवस्था में पेंडिंग पड़े केस ही बड़ी समस्या है।

प्राइवेट काम के लिए मिले अधिक मुआवजा : प्रो. शेफर ने बताया कि वे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भूमि अधिग्रहण के मामले में अगर प्राइवेट योजना के लिए जमीन ली जा रही है तो उसका मुआवजा अधिक होना चाहिए। जबकि जनता से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए मुआवजे में रिआयत की गुंजाइश हो सकती है।

उपभोक्ताओं को अब बेहतर सुरक्षा व न्याय

कानपुर: उपभोक्ताओं को अब और बेहतर सुरक्षा व जल्द न्याय मिलेगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) की महसभा में नया रेसोलूशन पास किया गया है। इसके अंतर्गत भारत में भी इसकी कार्यप्रणाली बनाई जाएगी। इस संबंध में यूएनओ महासचिव की अक्टूबर में इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट बॉडी मीटिंग होने जा रही है। यह जानकारी आईआईटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के सदस्य डॉ. बीएस गुप्ता ने दी।

लॉ एंड इकोनोमिक्स पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने बताया कि अभी तक जो नियम हैं उनके अनुसार उपभोक्ता को तीन महीने के अंदर राहत मिल जानी चाहिए। फिर भी पेचीदे मामलों में अधिक समय लगता है। ऐसे ही मामलों का निस्तारण जल्द करने के लिए रेसोलूशन तैयार किया गया है।

नेशनल कंज्यूमर फोरम में दस हजार मामले लंबित : डॉ. गुप्ता ने बताया कि प्रयासों के बाद भी कई मामलों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है। नेशनल कंज्यूमर फोरम में दस हजार मामले लंबित हैं। जो मामले फंसे हुए हैं उनमें सर्वाधिक बिल्डर्स से संबंधित हैं। इनमें ऐसे मामले अधिक हैं जिनमें बिल्डर्स ने वादा करने के बाद समय पर उपभोक्ता को फ्लैट व मकान आवंटित नहीं किया है जबकि आवास के एवज में रुपए लिए जा चुके हैं।

बेहतर सुविधाएं मिलेंगी : उपभोक्ताओं के लिए जो नए नियम जोड़े जा रहे हैं उससे उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन लोगों पर उपभोक्ता अदालतों का शिकंजा और कड़ा होगा जो नियमों की अनदेखी करते हैं।

विवेकपूर्ण होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सचिव स्मिता झिंगरन ने कहा कि प्रतिस्पर्धा विवेकपूर्ण होनी चाहिए। हमारे देश में असंगठित बाजार का प्रतिशत बहुत अधिक है। ऐसे बाजार के लिए लॉ एंड इकोनोमिक्स कोई मायने नहीं रखती है।

श्रीमद्भागवत गीता से मिलती है ऊर्जा : शेफर

कानपुर: आईआईटी में लॉ एंड इकोनॉमिक्स विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे बुसरिस लॉ यूनिवर्सिटी जर्मनी के प्रो. हैंस बर्न्ड शेफर की आस्था भारतीय धर्म ग्रंथों में है। उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता, रामायण, महाभारत व वेद पढ़े हैं। शेफर बताते हैं कि श्रीमद्भागवत गीता से उन्हें ऊर्जा मिलती है। भारतीय संस्कृति से उन्हें बेहद लगाव है। यहां का रहन सहन व खान पान उन्हें खूब भाता है। वे बताते हैं कि जर्मनी समेत अन्य देशों में जब वे होटल में खाना खाने जाते हैं तो भारतीय व्यंजन ही आर्डर करते हैं। भारत आने के लिए वे उत्साहित रहते हैं। यहां आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। आईआईटी कैंपस उन्हें पसंद आया है।